क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लम्बाई (कि.मी)
17	मेघालय	1	133
18	मिजोरम	3	441
19	नागालैंड	1	220
20	उड़ीसा	4	837
21	पांडिचेरी	2	104
22	पंजाब	5	980
23	राजस्थान	5	1709
24	सिक्किम	1	30
25	तमिलनाडु	16	3355
26	त्रिपुरा	1	135
27	उत्तर प्रदेश	4	1856
28	पश्चिम बंगाल	7	530
		135	39388

एल .पी. जी .पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गो का आवंटन

235.**श्री रामजी लाल**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल एलपीजी एजेन्सिया और पेट्रोल स्टेशनों /बिक्री केन्दो का कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूतिच जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या सरकार यह सुविधा देश में अन्य पिछड़े वर्गो को भी उपलब्ध करायेगी जोकि देश की जनसंख्या के 27 प्रतिशत हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) (क) विद्यमान नीति के मुताविक तेल चयन बोर्डो के माध्यम से आवंटित की गई

।

डीलरशिपों / डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

(ख) और (ग) वर्द्यमान में डीलरशिपों /- डिस्ट्रीब्यूटरिशपों के आवंटन में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहार्य नही है । वे आरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत विद्यमान श्रेणियों के अधीन अवसरों से लाभ उठा रही हैं।

कमांडो के प्रशिक्षण में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की अनुपस्थिति

236.**श्री नागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में कमांडों का प्रशिक्षण ले रहे 147 सब- इसंपैक्टर अनुपस्थित पाये गये हैं।

((ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) अब तक सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो . एम .कामसन) : (क) से (ग) प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 132 परिवीक्षीधीन उप-निरीक्षक ,1/2 जुलाई , 1955 की रात्रि के दौरान हाजिरी लेने पर उस समय अस्थायी रूप से अनुपस्थिति पाए गये थे जब वे अपना कमांडो कैपसूल पाठ्यक्रम कर रहे थे पूछताछ करने पर पाया गया कि उनमें से 85 वास्तव में साथ के मनोरंजन कक्ष में टेलीविन पर एक फिल्म देख रहे थे । इन सभी को लिखित रूप में चेतावनी जारी कर दी गई हैं। परिवीक्षाधीन 47 उप-निरीक्षकों, जो बिना अनुमति के परिसर छोड़कर चले गए थे. में से 43 उप-निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए । तदनुसार, इन सभी 43 उप-निरीक्षकों की सेवाओं को उनकी अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दिया गया था। तथापि, अनुशासनात्मक अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील किए जाने पर इन चारों को सेवा में पुनः वापस ले लिया गया हैं।

दिल्ली परिवाहन निगम द्वारा उठायी गई हानियां

237.**श्री इकबाल सिंह** : क्या जल-भूतल परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष भारी वित्तियां हानियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 ,1994-95 और 1995-96 के प्रथम 9 महीनों के दौरान डी.टी.सी के कितनी राशि की हानि हुई ;

(ग) डी.टी.सी को प्रतिवर्ष को रही हानि के प्रमुख कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार इन वित्तीय हानियों को देखते हुए डी.टी.सी के अनावश्यक प्रशासनिक व्यय में कमी करने तथा उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने पर विचार कर रही हैं; और

(ड) यदि हां.तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं?

i

जल - भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरें इस प्रकार हैं:-

		(करोड़ रू)
वर्ष	कार्यशीलघाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास को छोड़कर)	कुल घाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास सहित)
1993-94	83.60	281.84
1994-95	68.27	307.04
1995-96	68.61	299.70
(दिसम्बर, 95 तक)		

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को घाटा निम्न किराए ढांचे , प्रचालन की बढ़ती लागत, फालतू स्टाक और सामजिक दायित्व आदि के कारण हो रहा हैं।

(घ) और (ड) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) दि.प.नि. के फालतू स्टाफ को कम करने के लिए इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम शुरू करना ।

(2) दि.प. नि. के किराए ढांचे को दि. 21.6.94 से युक्तिसंगत बनाना ।

(3) जनशक्ति अनुपात में कमी ।

(4) भर्ती पर प्रतिबंध

(5) घाटे वाले और लाभ वाले रूटों का सतत् रूप से वास्तविक संतुलन बनाया जा रहा हैं ।

Sanction of Telephones on the Recommendations of M.P.s

238. SHRI SHIV CHARAN SINGH: will the Minister of COMMUNiCA TIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recommendations of MPs for Sanction of Telephone connections on an out of turn